

सुप्रीम न्यूज

जनता का अखबार

वर्ष : 13 अंक : 296 गौतमबुद्धनगर, शनिवार, 31 दिसम्बर 2022 उत्तर प्रदेश से प्रकाशित पृष्ठ : 04 मूल्य : 05 रूपये मात्र

नोएडा पुलिस की कमान बदलने से दरोगाओं के होंसले बुलंद

नोएडा। नोएडा के सेक्टर 8,9,10 में वर्षों से तस्करों का गढ़ बना हुआ था। जिस पर अब अंकुश लगाने लगा है। जिसमें झुंडपुरा चौकी प्रभारी मादक पदार्थों की बिक्री और तस्करी को रोकने में जोर शोर से कदम उठाते दिखाई दे रहे हैं। अवैध मादक पदार्थ की तस्करी करने वालों पर चौकी प्रभारी की ताबड़तोड़ कार्रवाई को देखकर बहुत से तस्कर क्षेत्र छोड़कर भाग रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में झुंडपुरा चौकी प्रभारी अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए नजर आ रहे हैं। झुंडपुरा चौकी प्रभारी दरोगा संजय पूनिया ने पंद्रह दिन पहले ही चौकी प्रभारी के रूप में चार्ज संभाला है। जिसके बाद से अब तक



की गई कार्रवाई में दर्जनों शातिर बदमाशों को जेल भेजा गया है। जिनमें से पांच गांजा तस्कर व चार अवैध शराब तस्कर पकड़ कर जेल भेजे गए हैं। जिनमें एक महिला गांजा तस्कर तारा को भी चौकी प्रभारी संजय पूनिया

द्वारा जेल भेज दिया गया है। जबकि इस चौकी के क्षेत्र में सफेद पोशों द्वारा संरक्षित शातिर गांजा तस्कर महिलाएं बहुत से नाबालिक बच्चों, विकलांगों से तस्करी का कारोबार करवाते हैं। अब ऐसे लोग पुलिस की सख्त कार्रवाई को देखकर छटपटा रहे हैं। बहुत से तस्कर अपने अवैध कार्यों को बंद कर अपने बचाव के लिए आकाओं की शरण में पहुंच गए हैं। अगर विभाग के उच्चाधिकारियों द्वारा अवैध कार्यों पर प्रतिबंध लगाने वाले पुलिस कर्मियों को प्रोत्साहित किया जाए तो अन्य पुलिस कर्मी भी अपराधियों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई करने व अवैध कार्यों को जड़ से नेस्तनाबूत करने में रुचि लेने लगेंगे। पुलिस की इस तरह

वर्षों से चल रहे नशे के काले कारोबार के मकड़जाल को तेज तर्रार चौकी प्रभारी संजय पूनिया ने कुछ ही दिनों में तोड़ दिया है। नोएडा वासियों का कहना है कि नोएडा पुलिस की कमान बदलने से इमानदार दरोगाओं के होंसले बुलंद हो गए। नशे के काले कारोबार के नाम से बदनाम हुए क्षेत्र को निजात दिलाने के लिए पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाई होने से ऐसा लग रहा है कि अब नशे के कारोबार में लिप्त शातिर महिला तस्करों का भी नंबर जल्द आ जाएगा। साथ ही यह भी लग रहा है कि नशे के काले कारोबार को संरक्षण दे रहे सफेद पोश भी पुलिस कार्रवाई की जद में आएंगे।



की कार्यवाहियों से तस्करों के चुंगल में पढ़ाई लिखाई और किसी अन्य अच्छे फंसे. नाबालिक बच्चे व महिलाएं भी कार्य की ओर ध्यान देना शुरू कर देंगे।

सड़क दुर्घटना में क्रिकेटर ऋषभ पंत घायल, कार में लगी आग

देहरादून। भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार क्रिकेटर ऋषभ पंत शुक्रवार सुबह उत्तराखंड के हरिद्वार जिले के रुड़की में सड़क दुर्घटना में घायल हुए। यह दुर्घटना कार के ड्रिवाइडर से टकराने से हुई। जिसके बाद कार में आग लग गई। उन्हें घायल अवस्था में देहरादून के मैक्स अस्पताल लाया जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है।

पुलिस सूत्रों के अनुसार ऋषभ पंत दिल्ली से मर्सिडीज कार से उत्तराखंड के रुड़की स्थित अपने घर आ रहे थे। आज सुबह लगभग साढ़े पांच बजे कोतवाली मंगलोर क्षेत्र के मोहम्मदपुर जट के पास उनकी कार अनियंत्रित होकर ड्रिवाइडर से टकरा गई। ड्रिवाइडर से टकराने के बाद कार में आग लग गई। किसी तरह क्रिकेटर और उनके साथ बैठे चालक



● पुलिस सूत्रों के अनुसार ऋषभ पंत दिल्ली से मर्सिडीज कार से उत्तराखंड के रुड़की स्थित अपने घर आ रहे थे। आज सुबह लगभग साढ़े पांच बजे कोतवाली मंगलोर क्षेत्र के मोहम्मदपुर जट के पास उनकी कार अनियंत्रित होकर ड्रिवाइडर से टकरा गई।

सहित एक अन्य व्यक्ति को कार से निकाला गया। सूचना मिलने पर मौके पर 108 और हरिद्वार पुलिस द्वारा घायलों को सर्वप्रथम रुड़की के

सक्षम अस्पताल ले जाया गया।

अस्पताल के चैयरमैन डॉ सुशील नागर ने बताया कि फिलहाल ऋषभ पंत की हालत स्थिर बनी हुई है। डॉक्टरों के मुताबिक ऋषभ के माथे और पैर में चोट आई है। उनको रुड़की से देहरादून के मैक्स अस्पताल रेफर किया गया है। वहां उनकी प्लास्टिक सर्जरी की जाएगी।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वाहन दुर्घटना में घायल क्रिकेटर ऋषभ पंत के बारे में अधिकारियों से जानकारी लेते हुए उनका समचित इलाज की हरसम्भव व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिये हैं। उन्होंने श्री पंत के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करते हुए कहा कि उनके इलाज का सारा व्यय राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। अगर एयर एम्बुलेंस की आवश्यकता होती है तो उसकी भी व्यवस्था की जाएगी।

उज्बेकिस्तान में कफ सिरप से बच्चों की मौत मामले में जांच शुरू

नई दिल्ली। भारतीय फार्मास्यूटिकल फर्म मैरियन बायोटेक की कफ सिरप के सेवन से उज्बेकिस्तान में कथित रूप से 18 बच्चों की मौत के मामले की जांच केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन ने शुरू कर दी है। यही नहीं सीडीएससीओ इस संबंध में उज्बेकिस्तान के राष्ट्रीय औषधि नियामक के नियमित संपर्क में है और घटना के संबंध में और जानकारी मांगी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि दवा कंपनी का निरीक्षण कर सैंपल लिए गए हैं और उन्हें जांच के लिए चंडीगढ़ स्थित केंद्रीय औषधि जांच प्रयोगशाला भेजा गया है। रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि एक रोज पूर्व उज्बेकिस्तान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने आरोप लगाया है कि भारतीय फर्म द्वारा निर्मित कफ सिरप से उसके यहां 18 बच्चों की मौत हो गई है। विभिन्न केंद्रीय एजेंसियों और उत्तर प्रदेश के औषधि विभाग के एक दल ने गुरुवार को नोएडा स्थित दवा कंपनी के कार्यालय का निरीक्षण किया।

10 साल से उज्बेकिस्तान भेजी जा रही



दवा-दवा फर्म के कानूनी सलाहकार हसन हरिस ने कहा कि इस प्रकरण पर हमें अफसोस है। सरकार मामले की जांच कर रही है। नमूनों की रिपोर्ट आने के बाद सब कुछ साफ होगा। फर्म की तरफ से दवा निर्माण में कोई कमी नहीं है। कंपनी पिछले दस वर्षों से उज्बेकिस्तान में दवा की आपूर्ति कर रही है। कभी भी इस तरह की शिकायत नहीं आई है। जांच के बाद ही सब कुछ साफ हो जाएगा।

ओवरडोज हो सकता है मौत का कारण फर्म को केवल बाहर दवा आपूर्ति करने की अनुमति है। नोएडा के जिला औषधि निरीक्षक ने कहा कि उज्बेकिस्तान की मीडिया रिपोर्ट के

मुताबिक ओवरडोज (अत्यधिक मात्रा में दवा का सेवन) और बिना प्रिस्क्रिप्शन (बिना डाक्टर की सलाह) दवा के सेवन से बच्चों की मौत की आशंका है।

प्राथमिक जांच दवा में नहीं मिली कोई अनियमितता-उज्बेकिस्तान भेजी गई कफ सिरप का निर्माण मई-2021 में हुआ था। इसकी एक्सपायरी अप्रैल-2024 है। सिरप की जून में आपूर्ति की गई थी। फार्मास्यूटिकल कंपनी ने कहा कि अक्टूबर 2022 से संबंधित कफ सिरप का उत्पादन नहीं हुआ है। जांच रिपोर्ट आने तक इस कफ सिरप के उत्पादन पर रोक लगाई गई है। मंगलवार के बाद बृहस्पतिवार को भी औषधि विभाग की टीम ने दवा फर्म पहुंचकर तीन अलग-अलग कफ सिरप के सैंपल लिए। अब तक पांच कफ सिरप के नमूने लिए जा चुके हैं। उज्बेकिस्तान के मंत्रालय के मुताबिक प्रयोगशाला में जांच के दौरान सिरप के एक बैच में रासायनिक एथिलीन ग्लाइकोल पाया गया, जो कि हानिकारक होता है।

संपादकीय

आखिर मादक पदार्थों की बिक्री क्यों नहीं रुकती ?



पुलिस और पत्रकारों की मिली भगत से अवैध शराब, गांजा, सुल्फा, सट्टा आदि की तस्करी का बहुत बड़ा कारोबार है। खाईवाडी करने वाला लाखों रुपए महीने पत्रकारों और पुलिस को मंथली के रूप में देते हैं। अब आप ये मत समझ लेना कि मंथली का रोग पत्रकारों और पुलिस विभाग तक ही सीमित है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अवैध कारोबार करने वाले तथाकथित समाज सेवकों और राजनीति से जुड़े अधिकांश तथाकथित नेताओं की सेवा भी करते हैं। मतलब हमाम में सब नंगे हैं। ये सभी बातें अब बहुत आम बात है। भले ही ये सभी बातें पत्रकारों द्वारा जनता के सामने कभी भी नहीं रखी गईं। छोटे लोग अपराध से सीधे तौर पर जुड़े होते हैं। लेकिन यह भी सच्चाई है कि अनेकों सफेद पोश इस तरह के अवैध धंधों से मंथली बांध कर रखते हैं। जिसके चलते अवैध धंधों को बड़े-बड़े सफेद पोश मगरमच्छ का संरक्षण प्राप्त होता है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि पत्रकारों और अन्य सफेद पोशों की मंथली भी पुलिस ही मैनेज करती है। इसका सीधा मतलब यह हुआ कि पत्रकार पुलिस की अवैध और गैरकानूनी गतिविधियों पर पर्दा डालें रखते हैं। जिसके बदले में पुलिस ही पत्रकारों को अवैध धंधों के संचालकों से महावारी सुविधा शुल्क दिलवाती है। यह सब आपको अजीब सा लग रहा होगा। लेकिन अब यही एक बड़ी सच्चाई है। ये सब हम पाठकों को इस लिए बता रहे हैं कि आप जब भी कोई अवैध कारोबार अपने आसपास होता देखें तो ऐसे अवैध कारोबारियों के साथ उठने, बैठने वाले लोगों पर ध्यान दें। थोड़ा सा ध्यान देते ही आप स्वयं सब कुछ अपनी आंखों से देखेंगे। और समझ जाएंगे कि आखिर चल क्या रहा है? वास्तव में मेहनत करके तो केवल मजदूर और किसान वर्ग ही खाता है। बाकी सब तो केवल मजदूरों और किसानों को किसी न किसी तरह दुहते रहते हैं। कानून भी है और कानूनों को सख्ती से लागू करने के लिए बहुत बड़ा कानूनी तंत्र भी मौजूद है। महा नगरों में तो पत्रकारों और समाजसेवियों की संख्या भी हजारों में होती है। वो भी कोई अकेले नहीं होते। पूरी की पूरी फौज संघटित रूप से होती है। बड़े मीडिया संस्थानों के अलावा पत्रकारों के संगठन भी होते हैं फिर भी हैरानी की बात यह है कि मादक पदार्थों की तस्करी जैसा अपराध नहीं रुकता।

कुछ सिख गुजरातियों से लीजिए - इंजिनियर लख्मीचंद यादव



लख्मीचंद

यदि जीवन में कामयाब बनना चाहते हो और अपनी जिंदगी को खुशाल और बेहतर बनाना चाहते हो तो आप लोग कुछ

सिख गुजरातियों से लीजिए-इंजीनियर लख्मीचंद यादव। देखिए जिसके पास देश में सबसे बड़ा ओहदा है आज उस मां के संस्कारी पुत्र ने सुबह सुबह दिल्ली से गुजरात जाकर अपनी पूजनीय मां को कंधा दिया और अंतिम स्व यात्रा वाहन में बैठकर वो मां के शव के साथ श्मशान घाट पहुंचे और श्मशान घाट में अपनी मां का अंतिम संस्कार किया फिर कुछ ही देर बाद उन्होंने बिना विलंब किये ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कई बड़ी परियोजनाओं की जनता को सौगात दी ऐसा करके आज श्री नरेन्द्र मोदी जी ने देश ही नहीं पूरी दुनिया का भी दिल जीत लिया।

वही जब गुजरात में कोई इंसान मरता है वहां रोना पीटना नहीं होता और नाहीं वहां लगातार 13 दिन लोग शोक प्रकट करने शोकाकुल परिवार के घर जाते हैं वहां



सिर्फ एक दिन भगवान से प्रार्थना सभा की जाती है उसी दिन सब लोग जाते हैं बाकी दिन नहीं। हमारी यूपी में लोग शोकाकुल परिवार की खाना व चाय पानी में ही कमर तोड़ देते हैं क्योंकि लगातार 13 दिन तक बड़ी तादात में लोग शोकाकुल परिवार के घर ढाढस बांधने पहुंचते हैं गुजरात इसी वजह से आज देश का सबसे धनी और खुशहाल राज्य बन गया है वीवीआइपी कल्चर को महत्व नहीं देते गुजराती तभी तो श्री मोदी जी ने लाल बत्ती पर ब्रेक लगा दिया बिल्कुल सादा जीवन जीते हैं गुजराती। उस परम पूजनीय मां हीरा बेन जी के चरणों में हम शत शत नमन और विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं जिन्होंने अपनी कोख से श्री मोदी जी जैसे सच्चे समाज भगत और सच्चे देश भगत बेटे को जन्मा है आई सेल्यूट आदरणीय माता जी।

वर्ष 2023: सार्थकता की तलाश

भारत डोगरा

वर्ष का समय आशा और उम्मीद का समय होता है। चाहे समस्याएं कितनी भी रहें, हम यही सोचना चाहेंगे कि नया वर्ष समस्याओं के समाधान को लेकर आए, भविष्य के लिए अच्छा संदेश लेकर आए।

यह हम अपने लिए भी सोचते हैं, अपने परिवार व प्रियजनों के लिए भी तथा सारी दुनिया के लिए भी। वर्ष का आरंभ ऐसा समय भी है जब हम तन-मन से कई तरह की अच्छी शुरुआत के लिए, कई शुभ संकल्पों के लिए अधिक तत्पर व तैयार होते हैं। मेहनत और निष्ठा के बल पर क्या हम वह लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण तो है पर पीछे छूटा जा रहा है?

क्या हम ऐसी किसी बुरी आदत या व्यसन से इस नये वर्ष में छुटकारा प्राप्त कर लेंगे, जिससे पीछा छुड़ाना बहुत समय से चाह रहे हैं?

इस तरह की सोच नये वर्ष में अधिक उमड़ती है और हम नये संकल्पों के लिए तैयार होते हैं। चाहे ऐसे सभी संकल्प हम पूरे न कर पाते हों, तो भी नये वर्ष का समय इस तरह के निर्णयों के लिए अधिक अनुकूल होता है और कई बार तो इन संकल्पों से बहुत बड़ी उपलब्धि वास्तव में प्राप्त हो जाती है। इस आशावादी नजरिए से देखें तो तमाम कठिनाइयों व अवरोधों के बावजूद, हम में से अधिकतर के पास अपने जीवन को बेहतर करने की, व उससे भी बड़ी बात यह है कि अपने जीवन के सुधार को दुनिया के, समाज के सुधार से जोड़ने की बहुत सी संभावनाएं मौजूद हैं।

आज सामाजिक स्तर पर इस तरह की सोच की बहुत जरूरत है कि घोर व्यक्तिवाद के इस युग में भी अधिक लोग अपनी प्रगति व बेहतरी का सामंजस्य पूरी दुनिया की प्रगति व बेहतरी से बनाने का प्रयास करें व इस दृष्टि से ही सोचने-समझने की प्रवृत्ति विकसित करें। आधुनिकता की मिथ्या समझ व प्रचार-प्रसार के असर में अनेक व्यक्ति शराब व अन्य नशे के आदि हो जाते हैं। इस नशे को छोड़ना एक ओर उनके स्वास्थ्य की रक्षा व उनके तथा उनके परिवार की भलाई के लिए जरूरी है, पर दूसरी ओर इससे समाज की भलाई और पर्यावरण की रक्षा भी जुड़ी है। शराब सामाजिक स्तर पर हिंसा, अपराध और दुर्घटनाओं का एक बहुत बड़ा कारण है और साथ में इसके उत्पादन की प्रक्रिया में बहुत पर्यावरण विनाश भी होता है।

इस तरह जो लोग नशा छोड़ते हैं वे अपनी और अपने परिवार की भलाई के साथ समाज की भलाई व पर्यावरण की रक्षा में भी अपना छोटा सा ही सही पर एक योगदान अवश्य कर रहे हैं। अनेक छोटे प्रयासों से ही बड़ा योगदान होता है। अतः लाखों लोग नशा छोड़ेंगे तो अपने आप यह सामाजिक व पर्यावरणीय योगदान भी बहुत बड़ा हो जाएगा। बड़ी संख्या में लोगों के दैनिक जीवन में हिंसा दुख-दर्द का एक बड़ा कारण है। बहुत आश्चर्य की बात है कि दैनिक जीवन की बहुत सी हिंसा अपने ही परिवार के सदस्यों के प्रति होती है। विश्व स्तर के घरेलू हिंसा के आंकड़े तो यही बताते हैं कि विश्व की

इस तरह छोटे प्रयासों का भी बड़ा असर हो सकता है; वर्ष 2023 में हम इस सोच को लेकर ही आगे बढ़ें तो इससे जीवन में नई आशा व नया उत्साह भी मिलने की पूरी संभावना है। हम तमाम कठिनाइयों के बावजूद बेहतर जीवन के लिए प्रयासरत हैं और अपने जीवन की बेहतरी के साथ दुनिया की बेहतरी में भी निरंतर योगदान दे रहे हैं-यह सोच निश्चय ही जीवन को एक मजबूत व सार्थक आधार देती है। तमाम अवरोधों के बीच, कठिनाइयों के बीच अपनी मेहनत, निष्ठा और दृढ़ निश्चय के आधार पर हम इस सार्थकता की राह को सफलता से अपना सकते हैं।



सबसे व्यापक स्तर पर होने वाली हिंसा दैनिक जीवन की हिंसा है, जिसकी मार सबसे अधिक महिलाओं को फिर बच्चों को झेलनी पड़ती है। यदि केवल शारीरिक हिंसा को न देखकर भावनात्मक

हिंसा को भी देखें तो यह और भी व्यापक है। इसके अतिरिक्त दैनिक जीवन की हिंसा में आस-पड़ोस की हिंसा व बदले की भावना से जुड़ी हिंसा भी शामिल है। यदि हिंसा व हिंसक सोच के दायरे से बाहर निकलने

का सोचा-समझा, सतत प्रयास किया जाए तो न केवल अपना व अपने परिवार का भला होगा अपितु सामाजिक स्तर पर भी हिंसा में कमी आएगी व हिंसा की निरर्थकता से मुक्त होने पर प्रगति की संभावनाएं भी बढ़ेंगी। इंसानियत की एक बहुत बुनियादी सोच है कि सभी लोगों की समानता और एकता में विश्वास रखना व धर्म, नस्ल, लिंग, रंग, क्षेत्र, जाति, वर्ग आदि के आधार पर भेदभाव न करना। जो लोग इस भेदभाव के निशाने पर हैं, उन्हें तो अपमान व अन्याय सहना ही पड़ता है पर जो यह भेदभाव करते हैं वे स्वयं भी अपनी भेदभाव भरी सोच की संकीर्णता में इसकी गिरफ्त में रहते हैं और इस कारण उदार व खुली सोच का जीवन नहीं जी पाते हैं, तरह-तरह की संकीर्णता व इससे जुड़ी हिंसक सोच से त्रस्त रहते हैं। यदि इसके स्थान पर वे यह सोचा-समझा व सतत प्रयास करें कि हमें बिना किसी भेदभाव के सभी मनुष्यों को समानता व एकता की सोच पर आधारित ही जीवन जीना है और सोच अपनानी है तो इससे उनका अपना जीवन निश्चित तौर पर बेहतर होगा व साथ में वे एक समानता व एकता पर आधारित समाज, देश व दुनिया को बनाने में भी अपना योगदान देंगे। 'वसुधैव कुटुम्बकम्' यानी पूरी दुनिया ही अपना परिवार है-यह बहुत सार्थक सोच है और जी-20 की अपनी अध्यक्षता के वर्ष में भारत ने इसे जी-20 के लिए यह कहते हुए अपनाया है कि यह तो हमारी प्राचीन संस्कृति का संदेश है।

हमारे सामने आज भी शहीद भगत सिंह का यह सवाल खड़ा है कि वास्तव में अन्याय, विषमता और भेदभाव दूर करने के कितने प्रयास हुए हैं व हो रहे हैं, उन्हें कितना महत्व मिल रहा है-स्थानीय स्तर पर, देश व दुनिया में। अतः यदि हम अपनी भलाई को समाज व दुनिया की भलाई के साथ जोड़ कर आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमें यह भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि इस प्रयास को पूरी ईमानदारी से ही किया जाए।

केवल अपने कैरियर या बिजनेस की सोच संकीर्ण सोच है, पर यदि अपने जीवन-यापन की जिम्मेदारी का सामंजस्य वि, समाज व देश की भलाई से जोड़ा जाए तो यह सही अर्थ में सार्थक रहेगी। इस तरह के लाखों प्रयास एक साथ होंगे तो इससे पूरा समाज बेहतर बनेगा व ऐसे प्रयास अधिकांश देशों में होंगे तो बेहतर दुनिया बनेगी। इस तरह छोटे प्रयासों का भी बड़ा असर हो सकता है; वर्ष 2023 में हम इस सोच को लेकर ही आगे बढ़ें तो इससे जीवन में नई आशा व नया उत्साह भी मिलने की पूरी संभावना है। हम तमाम कठिनाइयों के बावजूद बेहतर जीवन के लिए प्रयासरत हैं और अपने जीवन की बेहतरी के साथ दुनिया की बेहतरी में भी निरंतर योगदान दे रहे हैं-यह सोच निश्चय ही जीवन को एक मजबूत व सार्थक आधार देती है। तमाम अवरोधों के बीच, कठिनाइयों के बीच अपनी मेहनत, निष्ठा और दृढ़ निश्चय के आधार पर हम इस सार्थकता की राह को सफलता से अपना सकते हैं।

केजरीवाल सरकार ने दिल्ली की नई ड्राफ्ट सोलर-पॉलिसी को दी हरी झंडी

नई दिल्ली। दिल्ली को इलेक्ट्रिक व्हीकल कैपिटल बनाने के बाद दिल्ली को सौर ऊर्जा खपत में भारत का अग्रणी राज्य बनाने के लिए केजरीवाल सरकार ने दिल्ली की नई सोलर-पॉलिसी के मसौदे को हरी झंडी दी।

दिल्ली सोलर-पॉलिसी 2022 के मसौदे का उद्देश्य 2025 तक 6000 मेगावाट स्थापित सौर क्षमता का लक्ष्य स्थापित करना है। ताकि अगले 3 सालों में दिल्ली की वार्षिक बिजली मांग में सौर ऊर्जा की हिस्सेदारी 9 प्रतिशत से बढ़ाकर 25 प्रतिशत की जा सके, जो देश में सबसे ज्यादा होगी। पॉलिसी ड्राफ्ट को उपमुख्यमंत्री की मंजूरी मिलने के बाद अब स्टेकहोल्डर्स की टिप्पणियों के लिए नीति को 30 दिनों के लिए सार्वजनिक डोमेन में रखा जाएगा। इसके बाद इसे अंतिम मंजूरी के लिए कैबिनेट के पटल पर रखा जाएगा। इस नीति के विषय में साझा करते हुए उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि नई सोलर-पॉलिसी दिल्ली में आवासीय और वाणिज्यिक उपभोक्ताओं के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (जीबीआई) और पूंजीगत

सब्सिडी के माध्यम से कई तरह के लाभ प्रदान करेगी। उन्होंने कहा कि इस नीति के साथ, हमारा उद्देश्य दिल्ली को न केवल



भारत बल्कि दुनिया में सौर ऊर्जा खपत के क्षेत्र में अग्रणी बनाना है।

उन्होंने आगे कहा कि दिल्ली की नई सोलर-पॉलिसी 2022- उद्योगों, उपभोक्ताओं, सरकारी संस्थाओं, वित्तीय संस्थानों और स्वच्छ ऊर्जा थिंक टैंक के साथ व्यापक हितधारक परामर्श के बाद दिल्ली संवाद और विकास आयोग

(डीडीसीडी) द्वारा तैयार किया गया है। इस पॉलिसी का उद्देश्य क्लीन एनर्जी के रूप में सौर ऊर्जा की खपत बढ़ाने के

साथ दिल्ली में 12,000 से अधिक हरित रोजगार सृजित करना भी है। सिसोदिया ने साझा करते हुए कहा कि दिल्ली में अब 500 वर्ग मीटर या उससे ज्यादा रूफटॉप एरिया वाली राज्य सरकार की सभी संपत्तियों पर सोलर प्लांट लगाना अनिवार्य है। इसे चरणबद्ध तरीके से क्रियान्वित किया जाएगा और इस नीति

की परिचालन अवधि 3 साल के भीतर पूरा किया जाएगा।

वहीं डीडीसीडी के उपाध्यक्ष जैस्मीन शाह ने कहा कि दिल्ली की नई सोलर पॉलिसी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में वायु प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन से लड़ने के दिल्ली के प्रयासों में मील का पत्थर साबित होगी।

उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार के थिंक टैंक के रूप में डीडीसीडी को उद्योग और उपभोक्ताओं के साथ व्यापक हितधारक परामर्श के बाद दिल्ली के लिए एक प्रगतिशील सोलर-पॉलिसी का मसौदा तैयार करने के प्रयास का नेतृत्व करने पर गर्व है।

मासिक उत्पादन-आधारित प्रोत्साहन (जीबीआई) के तहत आवासीय, गुप हाउसिंग सोसायटियों (सीजीएचएस), आरडब्ल्यूए, वाणिज्यिक और औद्योगिक (सी एंड आई) उपभोक्ताओं के लिए सिस्टम चालू होने की तारीख से पांच साल के लिए मासिक जीबीआई मिलेगा, बशर्ते सिस्टम परिचालन अवधि (3 साल) के भीतर चालू हो।

मासिक जीबीआई क्या होगा ?

-3 किलोवाट तक के आवासीय सोलर सिस्टम के लिए 3 रुपये/किलोवाट

- 3 किलोवाट से ऊपर और 10 किलोवाट तक के आवासीय सोलर सिस्टम के लिए 2 रुपये/किलोवाट

-सीजीएचएस और आरडब्ल्यूए के लिए 500 किलोवाट (प्रति घर 10 किलोवाट पर) तक सौर प्रणाली वाले आरडब्ल्यूए के लिए 2 रुपये/केडब्ल्यूएच उपभोक्ताओं को प्रदान किया जाएगा।

-पहली बार 200 मेगावाट सौर परिनिर्माण के लिए सी एंड आई उपभोक्ताओं को 1 रुपये/किलोवाट की प्रारंभिक जीबीआई दी जाएगी।

-आवासीय उपभोक्ताओं को, पूंजीगत सब्सिडी के तहत प्रति उपभोक्ता 2,000 रुपये प्रति किलोवाट रुपये की दर से पूंजीगत सब्सिडी प्रदान की जाएगी जो अधिकतम 10,000 रुपये होगी और बिजली बिलों में एडजस्ट की जाएगी।

-आरटीएस से उत्पादन पर कर और शुल्क नहीं लगाया जाएगा, चाहे वह स्वयं के उपभोग के लिए हो या ग्रिड को आपूर्ति के लिए।

मोहल्ला क्लीनिकों में टेस्टिंग सर्विस के प्रस्ताव को एलजी ने दी मंजूरी

नई दिल्ली। दिल्ली के मोहल्ला क्लीनिकों में टेस्टिंग सर्विस को और आउटसोर्सिंग करने के लिए दिल्ली सरकार के प्रस्ताव को उपराज्यपाल (एलजी) ने मंजूरी दे दी है। हालांकि इसे दिल्ली सरकार के अस्पतालों में डायग्नोस्टिक सेवाओं को मजबूत करने के बजाए प्राइवेट आउटसोर्सिंग का प्रयास मानते हुए उन्होंने गंभीर आपत्ति भी जताई है। प्रस्ताव के तहत तीन प्राइवेट वेंडर मोहल्ला क्लीनिकों को डायग्नोस्टिक सेवाएं देंगे। एलजी ने कहा है कि पुराना अनुबंध 31 दिसंबर को खत्म हो रहा है ऐसे में प्रस्ताव मंजूर करने के अतिरिक्त और कोई विकल्प नहीं है।

एलजी ने समय कम होने के चलते टेस्टिंग सर्विस की आउटसोर्सिंग के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, लेकिन फाइल पर अपनी टिप्पणी में कहा है कि 2022 में मोहल्ला क्लीनिकों की संख्या 450 से बढ़कर 519 हो जाने के बावजूद मरीजों की संख्या 3,416 (वर्ष 2021) प्रति महीना से कम होकर इस साल 1,824 मरीज प्रति महीना हो गई है। मरीजों की संख्या तो कम हुई, मगर 2021 में 6,30,978 टेस्ट हर महीने से बढ़कर 2022 में 9,30,000 टेस्ट प्रति महीने हो गए। एलजी ने पिछले तीन साल में लैब टेस्ट की गुणवत्ता को लेकर एसेसमेंट स्टडी कराने की सलाह भी दी है।

इससे पहले उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने एलजी को चिठ्ठी लिखी थी कि दिल्ली सरकार के अस्पतालों और मोहल्ला क्लीनिकों में लैब सेवाओं के लिए

अनुबंध 31 दिसंबर को खत्म हो रहा है। नए अनुबंध पर तुरंत स्वीकृति की जरूरत है, ताकि नए



साल में एक जनवरी से फिर से काम शुरू हो वरना सभी अस्पतालों में टेस्ट बंद हो जाएंगे। एलजी कार्यालय की ओर से बताया गया कि दिल्ली कैबिनेट के 28 जुलाई के फैसले में यह तय किया गया था कि सरकारी अस्पतालों, डिस्पेंसरी, पॉलीक्लिनिक और हेल्थ कैंप में पुराने पैटर्न पर ही जोकि मोहल्ला क्लीनिकों में दिसंबर 2019 से चल रहा है, डायग्नोस्टिक सेवाएं आउट सोर्स की जाएंगी। कैबिनेट ने इसके लिए तीन प्राइवेट बिल्डर भी चुने, इसी को एलजी के सामने 12 दिसंबर को रखा गया था। अब एलजी कार्यालय के बयान में कहा गया है कि, मोहल्ला क्लीनिकों में चलने वाली डायग्नोस्टिक सेवाओं के लिए प्राइवेट वेंडर का अनुबंध दो साल का होता है और इसे दो बार बढ़ाया गया है। अब इसे और एक्सटेंशन देना मुमकिन नहीं था। समय पर निर्णय नहीं लेने की स्पष्ट चूक के कारण और अगस्त में बहुत पहले निर्णय लेने के बावजूद

सहमति के लिए उपराज्यपाल को फाइल नहीं भेजी गई। जब कोई निर्णय नहीं लिया गया तब भी वह

मीडिया में कुछ ऐलान करते रहें, जिसके बाद शर्मिंदगी से बचने के लिए 12 दिसंबर को फाइल उपराज्यपाल को भेजी। उल्लेखनीय है कि सिसोदिया ने 24 दिसंबर को केवल आठ कार्य दिवसों में एलजी को पत्र लिखकर मंजूरी का अनुरोध किया था। 12 दिसंबर को दिल्ली वालों को नए साल का तोहफा देते हुए दिल्ली सरकार ने अपने सभी अस्पतालों में 450 तरह के टेस्ट मुफ्त करने का फैसला लिया था। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सरकारी अस्पतालों और मोहल्ला क्लिनिक में 238 से अधिक जांच के लिए निःशुल्क व्यवस्था करने के स्वास्थ्य विभाग के एक प्रस्ताव को मंजूरी दे दी थी। वर्तमान में सरकार द्वारा मुफ्त में उपलब्ध कराए जाने वाले चिकित्सा परीक्षणों की संख्या 212 है। मुख्यमंत्री ने अस्पतालों और मोहल्ला क्लीनिकों में 238 और जांच निःशुल्क करने के स्वास्थ्य विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी थी, उसके बाद फाइल एलजी को भेजी गई थी।

निजामाबाद पीएफआई मामले में एनआईए ने 11 लोगों के खिलाफ दाखिल की चार्जशीट

नई दिल्ली। राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने प्रतिबंधित पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) द्वारा आतंकवादी प्रशिक्षण शिविरों के आयोजन और आतंकवादी गतिविधियों के लिए व्यक्तियों की भर्ती से संबंधित एक मामले में 11 लोगों के खिलाफ हैदराबाद की एक विशेष अदालत में आरोप पत्र दायर किया है। मामला शुरू में तेलंगाना के निजामाबाद जिले के पीएस 4 टाउन में दर्ज किया गया था। हालांकि, जांच को अगस्त 2022 में एनआईए ने अपने हाथ में ले लिया था।

एनआईए ने चार्जशीट में कहा, 'जांच से पता चला है कि आरोपी व्यक्ति भोले-भाले मुस्लिम युवाओं को कट्टरपंथी बना रहे थे और उन्हें भारत सरकार के साथ-साथ अन्य संगठनों और व्यक्तियों के खिलाफ नफरत और जहर भरे भाषणों के जरिए पीएफआई में भर्ती कर रहे थे।' एक बार भर्ती होने के बाद, मुस्लिम युवाओं को योग कक्षाओं और शारीरिक शिक्षा (पीई) शुरुआती पाठ्यक्रम (बीसी) की आड़ में पीएफआई द्वारा आयोजित प्रशिक्षण शिविरों में भेजा गया, जहां उन्हें रोजमर्रा की वस्तुओं (चाकू, दरांती और लोहे की छड़) के उपयोग में प्रशिक्षित किया गया था, ताकि किसी व्यक्ति के शरीर

के कमजोर अंगों, जैसे कि गले, पेट और सिर पर हमला करके उसे मार दिया जाए और आतंकी वारदातों को अंजाम दिया जा सके। आरोपी अब्दुल खदेर, अब्दुल अहद, शेख, इलियास अहमद, अब्दुल



सलीम, शेख, शादुल्लाह, फिरोज खान, मोहम्मद ओस्मान उर्फ उस्मान, सैयद याहिया समीर, शेख इमरान, मोहम्मद अब्दुल मुबीन और मोहम्मद इरफान पर धारा 120बी, 153 (ए) आईपीसी, धारा 17, 18, 18ए और 18बी यूए(पी) अधिनियम के तहत चार्जशीट किया गया है।

दिल्ली में कड़के की ठंड के बावजूद एक्वआई 'बेहद खराब' श्रेणी में

नई दिल्ली। कोहरे की हल्की परत के बावजूद दिल्लीवासियों को ठंड से राहत मिली है। राजधानी में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहा। भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के अनुसार, सुबह सफदरजंग वेधशाला में तापमान 11 डिग्री सेल्सियस और पालम क्षेत्र में 12 डिग्री सेल्सियस था।

सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च (सफर) के आंकड़ों के मुताबिक, ठंड के मौसम से राहत के बावजूद, राष्ट्रीय राजधानी में हवा की गुणवत्ता बहुत खराब श्रेणी में दर्ज की गई। शुक्रवार सुबह शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स (एक्वआई) 364 पर पहुंच गया। धीरपुर में एक्वआई बहुत खराब श्रेणी के तहत 356 पर पीएम 2.5 के साथ गंभीर श्रेणी में प्रवेश कर गया। विशेषज्ञों ने कहा कि शनिवार को भी हवा की गुणवत्ता बेहद खराब श्रेणी में रह सकती है। एक्वआई शून्य से 50 के बीच 'अच्छा', 51 और 100 के बीच 'संतोषजनक', 101 और 200 के बीच 'मध्यम',

201 और 300 के बीच 'खराब', 301 और 400 के बीच 'बेहद खराब' और 401 और 500 के बीच



'गंभीर' माना जाता है। पूसा में, एक्वआई ने पीएम 2.5 को 373 'बहुत खराब श्रेणी' में दर्ज किया। लोधी रोड पर, पीएम 2.5 सघनता के साथ वायु गुणवत्ता सूचकांक बहुत खराब श्रेणी के तहत 360 पर था और पीएम 10 खराब श्रेणी के तहत 280 पर था। आयानगर में पीएम 2.5 खराब श्रेणी में 355 जबकि पीएम 10 खराब श्रेणी में 277 पर पहुंच गया।

आगरा में कोरोना वायरस से संक्रमित पाए जाने के बाद लापता हुआ विदेशी पर्यटक

आगरा (उप्र), 1 आगरा में 26 दिसंबर को ताजमहल देखने गया एक विदेशी पर्यटक कोविड-19 से संक्रमित होने की पुष्टि होने के बाद लापता हो गया है। एक वरिष्ठ स्वास्थ्य अधिकारी ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। आगरा के मुख्य चिकित्सा अधिकारी (सीएमओ) डॉ. अरुण श्रीवास्तव ने कहा कि वे पर्यटक को ढूंढ नहीं पाए हैं क्योंकि उसने जो संपर्क जानकारी दी थी, वे गलत हैं। श्रीवास्तव ने कहा, हफ्ते पर्यटक 26 दिसंबर को ताजमहल देखने गया था और स्मारक के प्रवेश द्वार पर कोविड-19 परीक्षण के लिए नमूना लिया गया। उसकी आरटी-पीसीआर जांच रिपोर्ट में कोविड-19 से संक्रमित होने की पुष्टि हुई। हालांकि, पर्यटक द्वारा दिए गए संपर्क नंबर और अन्य विवरण गलत निकला, जिसके बाद से हम उसे ढूंढ नहीं पाए हैं। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग अब स्थानीय खुफिया इकाई (एलआईयू), होटल एसोसिएशनों व अन्य सूत्रों की मदद से पर्यटक की तलाश कर रहा है। उन्होंने कहा, ह्आगरा में स्वास्थ्य विभाग पर्यटक के ठिकाने का पता लगाने के लिए कदम उठा रहा है ताकि उसे उचित उपचार दिया जा सके और अन्य लोगों को भी संक्रमण से बचाया जा सके। श्रीवास्तव ने कहा, हमने होटल एसोसिएशनों से कहा है कि वे होटलों में ठहरे विदेशी पर्यटकों का विवरण प्रदान करें। पुलिस व एलआईयू से भी मदद ले रहे हैं। इसके अलावा अब से भविष्य के रिकॉर्ड के लिए नमूना संग्रह के समय प्रत्येक विदेशी पर्यटक का पहचान पत्र लिया जाएगा।

मऊ में राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज के छात्र को गोली लगी

मऊ, 1 उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के सरायलखंडी थाना क्षेत्र में स्थित राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज के तृतीय वर्ष के एक छात्र को बृहस्पतिवार को गोली लग गयी। बृहस्पतिवार को पुलिस ने यह जानकारी दी। नगर क्षेत्राधिकारी (सीओ)



धनंजय मिश्रा ने बताया कि गाजीपुर जिले का रहने वाला साहिल (22) यहां राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज में तृतीय वर्ष का छात्र है। उन्होंने बताया कि छात्र को गोली लगने के बाद उसके साथियों ने जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया, जहां चिकित्सकों ने स्थिति गंभीर देखते हुए उसे आगे भेज दिया। सीओ ने बताया, ह्आगरा के बाद जब हम लोग घटनास्थल पर पहुंचे और सीसीटीवी फुटेज जांचा गया तो मामला कुछ समझ में नहीं आया। इसके बाद हमलोग छात्र के कमरे में पहुंचे जहां पर प्रथम दृष्टया देखने को मिला कि उसके कमरे में जो चादर रखा है वह भी खून से सना हुआ है। उन्होंने आशंका जतायी कि छात्र को गोली उसके कमरे में ही लगी है। हालांकि सीओ ने कहा कि मामले की छानबीन की जा रही है और जल्द ही असलियत सामने आ जाएगी।

सत्संग में हिस्सा लेने आई पंगत के साधु का शव फंदे से लटका मिला

बाराबंकी, 1 उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले के फतेहपुर थाना क्षेत्र में सत्संग कार्यक्रम में हिस्सा लेने आए प्रयागराज के एक साधु का शव सदिग्ध हालात में आश्रम के कमरे में फंदे से लटकता पाया गया। एक पुलिस अधिकारी ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मृत



साधु अपनी संगत का कोषाध्यक्ष था और पुलिस को मौके से एक कथित सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है। वहीं, पुलिस सूत्रों ने कहा कि 27 दिसंबर को भ्रमणशील पंचायतीय उदासीन बड़ा अखाड़ा प्रयागराज और हरिद्वार से 50 साधुओं की टोली सीतापुर से बेलहरा और पैतपुर होते हुए फतेहपुर पहुंची थी। उन्होंने बताया कि महंत महेश्वरदास और महंत अद्वैतानंद के साथ कई साधु पंचघरा मोहल्ले में स्थित बाबा उदासीन आश्रम में ठहरे थे, जिनमें टोली का कोषाध्यक्ष पंजाब निवासी रामदास (50) भी शामिल था। पुलिस सूत्रों के मुताबिक, बृहस्पतिवार को रामदास के कमरे का दरवाजा नहीं खुलने पर लोगों ने खिड़की से झांकर देखा तो फांसी से लटकता उसका शव नजर आया। उन्होंने बताया कि मौके पर 5 पहुंची पुलिस ने खिड़की के रास्ते अंदर जाकर दरवाजा खोला और शव के पास एक ह्आसुसाइड नोट पाया, जिसमें लिखा था-अपनों ने विश्वासघात किया है और आत्महत्या का जिम्मेदार मैं स्वयं हूँ। पुलिस क्षेत्राधिकारी रघुवीर सिंह और कोतवाल अनिल कुमार पांडेय ने आश्रम में मौजूद साधुओं के बयान लेने के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। कोतवाल ने बताया कि घटना की जांच की जा रही है और जल्द ही पूरे मामले का खुलासा किया जाएगा। सूत्रों के अनुसार, कुछ साधुओं ने पूछताछ में पुलिस को बताया कि रामदास के सहयोगी विमल ने बेलहरा गांव में पंगत के ठहराव के दौरान अखाड़े के कोष से दो लाख रुपये बिना बताए निकाल लिए थे। उन्होंने बताया कि विमल ने अपनी इस हरकत के लिए फोन पर माफी भी मांगी थी। सूत्रों के मुताबिक, पुलिस विमल की तलाश कर रही है।

सामुदायिक शौचालय में एक साथ लगवा दिया चार टॉयलेट सीट, निर्माण में खर्च हुए सात लाख

यूपी के बस्ती जिला स्थित रुधौली विकास क्षेत्र के धन्सा ग्राम पंचायत में बने सामुदायिक शौचालय परिसर में एक साथ चार टॉयलेट सीट लगाने का मामला सामने आया है। वहां कोई दरवाजा या दीवार भी नहीं बनाई गई है, जिससे परदा हो सके। सोशल मीडिया पर इसकी फोटो वायरल होने के बाद खलबली मच गई। आनन-फानन में शौचालय की सीट उखड़वा ली गई। प्रकरण संज्ञान में आने पर उप-जिलाधिकारी आनंद श्रीनेत ने बीडीओ केदारनाथ कुशवाहा के साथ समुदायिक शौचालय का निरीक्षण किया। ग्राम पंचायत सचिव व एडीओ पंचायत से शौचालय संबंधी प्रपत्र कार्यालय में प्रस्तुत करने को कहा। जानकारी मिली है कि ग्राम पंचायत धन्सा में लगभग सात लाख की लागत से सामुदायिक



शौचालय का निर्माण कराया गया है। जिसमें ग्रामीणों के नहाने के लिए चार स्नानागार, शौच आदि की व्यवस्था के लिए एक कमोड सहित चार शौचालय बना हुआ है। परिसर के अंदर खुली जगह में चार बेबी फ्रेंडली टॉयलेट बनवाए जाने थे लेकिन निर्माण कराने वाले जिम्मेदारों ने सामान्य टॉयलेट सीट लगा कर छोड़ दिया। शुक्रवार को उसी की फोटो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने लगी। विकासखंड के एडीओ पंचायत शैलेंद्र मणि

त्रिपाठी ने बताया कि प्रकरण में विकासखंड के तत्कालीन बीडीओ सुनील कुमार कौशल और तत्कालीन एडीओ पंचायत दयाराम ने उस समय तैनात पंचायत सचिव प्रमोद कुमार श्रीवास्तव को कमियों को दूर करने के लिए निर्देशित किया गया था। लेकिन उसके तुरंत बाद ही उनका स्थानांतरण हो गया। एडीओ पंचायत का कहना है कि सामुदायिक शौचालय में पाई लापरवाही को तत्काल रूप से निर्देशित कर सही कराया जा

रहा है। इससे पहले पिछले हफ्ते कुदरहा विकास खंड के गौरा धुंधा गांव में बने सामुदायिक शौचालय के एक कक्ष में दो टॉयलेट सीट लगवाने का मामला सामने आया था। जिसमें जांच के बाद मौजूदा और पूर्व ग्राम विकास अधिकारी निर्लंबित कर दिए गए थे। साथ ही लघु सिंचाई के अवर अभियंता के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई का निर्देश डीएम ने दिया था। इसके अलावा पूर्व व वर्तमान ग्राम प्रधान को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। जिला पंचायत राज अधिकारी नमिता शरण ने बताया कि जिले में 16 स्थानों पर बेबी फ्रेंडली शौचालय का निर्माण कराया गया है। सभी का सत्यापन कराया जा रहा है। इसके लिए संबंधित ब्लॉक के बीडीओ को इसकी जिम्मेदारी दी गई है।

कड़ाके की ठंड के साथ होगी नये साल की शुरुआत, सर्दी ढा रही सितम, कोहरे में छिपा सूरज

राजधानी लखनऊ में ठंड का कहर जारी है। मौसम विज्ञानियों का कहना है कि नए साल की सुबह कड़ाके की ठंड के साथ होगी। शुक्रवार को भी कोहरे और ठंड ने लखनऊ को घेरे रखा। गुरुवार को सीजन में पहली बार दृश्यता शून्य तक पहुंच गई। बुधवार देर रात तीन बजे से कोहरा छाना शुरू हुआ। उस समय 500 मीटर दृश्यता रही। इसके बाद सुबह साढ़े आठ बजे दृश्यता शून्य पहुंच गई। आधे घंटे तक यही स्थिति रही। नौ बजे के बाद दृश्यता बढ़ने लगी। करीब



11 बजे कोहरा छंटा और धूप निकली, लेकिन गलन से बनी रही। दोपहर 12 से साढ़े 12 बजे के बीच धूप ने लोगों को थोड़ी राहत दी। आंचलिक मौसम विज्ञान केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक

अतुल कुमार सिंह ने बताया कि वायु गति में कमी आने के कारण लखनऊ में कोहरा रहा। अधिकतम दृश्यता 800 मीटर रही। सुबह सात से नौ बजे तक राजधानी अत्यधिक कोहरे की

चपेट में रही। साढ़े आठ बजे दृश्यता शून्य हो गई। इसे अति सघन कोहरे के रूप में जाना जाता है, जिसके कारण सौर विकिरण कट ऑफ (कोहरे की परत से किरणें परावर्तित हो जाना) से दिन में अधिकतम तापमान में 1.4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई। आगामी दो दिनों तक मौसम ऐसा ही रहने का अंदेशा है। गुरुवार को अधिकतम तापमान 20.8 और न्यूनतम तापमान 7.4 डिग्री सेल्सियस रहा। नए साल में ठंड पूरे शवाब पर होगी।

मायावती बोलीं-यूपी सरकार के खेल निराले

भाजपा को बताया सांप्रदायिक विवाद पार्टी; कहा-मंत्रियों को रोड शो का चस्का लगा

बसपा सुप्रीमो मायावती ने योगी सरकार पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने भाजपा को सांप्रदायिक विवाद पार्टी बताया। कहा, "यूपी सरकार के खेल विचित्र और निराले हैं। इनके मंत्रियों को सरकारी पैसे पर रोड शो का चस्का लग गया है। भाजपा ने सोची-समझी साजिश के तहत निकाय चुनाव टाल दिया है। हेट स्पीच और मद्रसा सर्वे जैसे कामों में समय बर्बाद किया। निकाय चुनाव में OBC आरक्षण पर ध्यान केंद्रित करती, तो ऐसी दुखद स्थिति पैदा न होती।" दरअसल, मायावती ने शुक्रवार को यूपी और उत्तराखंड के पदाधिकारियों के साथ अहम बैठक की। इस दौरान उन्होंने वरिष्ठ पदाधिकारियों और जिला अध्यक्षों को मिशन 2024 को लेकर गांव-गांव जाकर काम करने को कहा। पार्टी का जनाधार बढ़ाकर रणनीति के साथ काम करने का निर्देश दिया। मायावती ने कहा, "चुनाव को हटाने के लिए षड्यंत्र पर उठे राजनीतिक



उबाल का फीडबैक लें। इसके बाद नए तरीके से अगले लोकसभा चुनाव की तैयारियों में कार्यकर्ताओं को लग जाना चाहिए। सरकार की कथनी और करनी में बहुत अंतर है। सरकार लगातार झूठा प्रचार करके लोगों को काफी निराश कर रही है। खासकर GST के जंजाल से बेहाल व्यापारी वर्ग आंदोलन करने को मजबूर हो गए हैं। देश के करोड़ों लोग अच्छे दिन के लिए तरस गए हैं। सरकारी वादे और घोषणाएं अब उन्हें काफी चुभने लगी हैं।" ग्लोबल इनवेस्टर्स समिट को लेकर सरकार के खर्च करने पर भी बसपा प्रमुख ने हमला बोला।

मायावती ने कहा, "वैसे जनहित और जन-कल्याण को लेकर यूपी सरकार का भी खेल भी विचित्र और निराले हैं। धन्ना सेठों के धन बल पर देश के चुनाव में रोड शो करने की कला के माहिर लोगों को अब सरकारी धन से विदेश में रोड शो करने का नया चस्का लग गया है। यह बहुत दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। बसपा प्रमुख ने कहा कि कांग्रेस और भाजपा दोनों ही आरक्षण विरोधी पार्टियां हैं। दोनों ने मिलकर पहले SC-ST वर्ग के उत्थान के लिए उनके आरक्षण के संवैधानिक अधिकार को लगभग निष्क्रिय और निष्प्रभावी बना दिया है। अब वही पूरा जातिवादी दोषपूर्ण रवैया

OBC वर्ग के आरक्षण के साथ हर जगह किया जा रहा है। इनकी इसी जातिवादी नीति के कारण सरकारी विभागों में इनके आरक्षण के हजारों पद वर्षों से खाली पड़े हैं। इस मामले में सपा की भी सोच, नीति और नीयत ठीक नहीं है। मायावती ने कहा, "बीजेपी शासित दो राज्यों कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच सीमा विवादों को लेकर तकरार और टकराव बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। भाजपा जब आंतरिक सीमा विवाद का समाधान नहीं निकाल पा रही है, तो अंतरराष्ट्रीय सीमा विवाद पर कैसे हल निकाल पाएगी। यूपी में सभी पार्टियों के नेता खुद को OBC का हमदर्द बता रहे हैं। चाहे वो सपा प्रमुख अखिलेश यादव हों या डिप्टी सीएम केशव मौर्य। गुरुवार को अखिलेश ने कहा, "भाजपा आरक्षण विरोधी है। आरक्षण खत्म करने की साजिश रच रही है। आज पिछड़ों का आरक्षण छीना। कल दलितों की बारी है।